

[2025] 1 एस.सी.आर. 869 : 2025 आई.एन.एस.सी 90

विजय उर्फ विजयकुमार

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1049)

16 जनवरी, 2025

[जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या मृतक की मृत्यु कारित करने का अपीलकर्ता का कार्य दंड विधान (भा.दं.वि.) की धारा 300 के अपवाद 1 के तहत "गंभीर और अचानक उकसावा" के दायरे में आता है, जिससे अपराध हत्या से कम होकर दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत गैर-इरादतन हत्या हो जाएगा।

निर्णय सार

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 1 के आवेदन को आकर्षित करने की पूर्वापेक्षा:

अभिनिर्धारित: प्रत्येक और हर उकसावा, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा आत्म-नियंत्रण का नुकसान होता है, हत्या के अपराध को गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित नहीं करेगा – केवल तभी जब उकसावा "गंभीर और अचानक" दोनों हो, अभियुक्त दंड विधान की धारा 300 के अपवाद 1 का लाभ दावा करने के लिए हकदार होगा – यदि गंभीरता या अचानकता में से कोई एक अनुपस्थित है, तो उकसावा हत्या को गैर-इरादतन हत्या में कम नहीं करेगा।

[कंडिका 18 - 20]

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 1 के घटक – चर्चा की गई:

अभिनिर्धारित: दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के तीन मुख्य घटक हैं: (i) अचानक

(अर्थात्, 'अपेक्षित' नहीं और उकसावा और गैर-इरादतन हत्या के बीच का अंतराल 'संक्षिप्त' होना) और गंभीर ("उचित व्यक्ति परीक्षण" लागू करके निर्धारित किया जाना) उकसावा; (ii) उकसावा के कारण अभियुक्त ने आत्म-नियंत्रण की शक्ति खो दी; और (iii) आत्म-नियंत्रण की अपनी शक्ति से वंचित होने के कारण, अभियुक्त ने पीड़ित की मृत्यु कारित की - *मैनसिनी बनाम लोक अभियोजन निदेशक*, 1942 ए.सी. 1 पर भरोसा किया गया। [कंडिका 21 - 24]

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों को बिना प्रभावित किए, अधीनस्थ न्यायालय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को आहूत कर सकते थे यदि वे वर्तमान मामले को गैर-इरादतन हत्या के दायरे में लाना चाहते थे - क्योंकि तथ्यों से प्रकट होता है कि मृतक ने अपीलकर्ता को (जो अपने दोस्तों के साथ था) गाली दी और थप्पड़ मारा जिससे एक झगड़ा हुआ और अपीलकर्ता ने पास में पड़ी एक सीमेंट की ईंट से मृतक को मारा - हालाँकि, मृतक की मृत्यु न तो पूर्व-नियोजित थी और न ही पूर्व-चिंतित और अभियुक्त भी निहत्था था - इससे यह साबित हुआ कि अपीलकर्ता ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया या क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य नहीं किया - दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है लेकिन सजा को पहले ही काटी गई अवधि तक कम किया जाता है। [कंडिका 29 - 35]

न्याय दृष्टान्त

मैनसिनी बनाम लोक अभियोजन निदेशक, 1942 ए.सी. 1 - अवलंबन।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम, 1872।

मुख्य शब्दों की सूची

अचानक और गंभीर; उकसावा; गैर-इरादतन हत्या; धारा 300, दंड विधान; धारा 300, दंड विधान का अपवाद 1; धारा 300, दंड संहिता का अपवाद 4; पूर्व-चिंतित; पूर्व-नियोजित; क्रूर ढंग; लाभ; आत्म-नियंत्रण।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1049/2021

मद्रास में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील सं. 194/2012 के दिनांक 27.06.2019 के निर्णय और आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

एम.पी. पार्थिवन, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

डी. कुमानन, सुश्री दीपा एस., शेख एफ. कालिया, विशाल त्यागी, चिन्मय आनंद, शगुफा खान, अधिवक्तागण, उत्तरदाता के लिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-6-2019 को आपराधिक अपील सं. 194/2012 में पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहां – अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार विचारण न्यायालय, अर्थात्, सत्र न्यायाधीश, नागापट्टिनम द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की, जिसमें यहां – अपीलकर्ता को भारतीय दंड विधान (इसके बाद, "भा.दं.वि." के रूप में संदर्भित) की धारा 304 भाग 1 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया और उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को भा.दं.वि. की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध का भी दोषी ठहराया गया था और उसे 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।
2. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है:-
3. यहां – अपीलकर्ता अपने दोस्तों सहित जिसमें 'अ. सा. 11' और 'अ. सा. 12' शामिल थे, दिनांक 5-11-2007 को एक फिल्म देखने गए थे। वे फिल्म देखने के बाद आधी रात को घर लौट रहे थे। जब वे एक पुल के नीचे सो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ मृतक

को एक शराबी हालत में पाया। ऐसा लगता है कि मृतक बहुत अधिक शराब के नशे में था। मृतक ने यहां – अपीलकर्ता और उसके दोस्तों के साथ एक झगड़ा शुरू कर दिया। अभियोजन के अनुसार, उस समय, अपीलकर्ता ने घटनास्थल पर पड़ी एक सीमेंट की ईंट उठाई और मृतक के सिर पर मारी। सिर की चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो गई।

4. अभियोजन का यह भी मामला है कि उसके बाद साक्ष्य को नष्ट करने की दृष्टि से, यहां – अपीलकर्ता ने मृत शरीर को आग लगा दी।
5. 'अ. सा. 1' ने ग्राम प्रशासनिक अधिकारी की अपनी क्षमता में संबंधित थाना में इस संबंध में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी) दर्ज कराई।
6. मृत शरीर का पंचनामा किया गया। उसके बाद, मृत शरीर को शव परीक्षा के लिए भेजा गया। शव परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि मृत्यु का कारण सिर की चोटें थीं।
7. अनुसंधान के अंत में, पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया। यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।
8. विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त वर्णित अपराध के लिए यहां – अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तैयार किया जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और विचारण की मांग की।
9. विचारण के दौरान, अभियोजन ने निम्नलिखित साक्षियों की जाँच की:-

अ. सा. 1. तिरु मोहन, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी

अ. सा. 2 श्रीमती रानी

अ. सा. 3 श्रीमती वनिता

अ. सा. 4 श्रीमती कविता

अ. सा. 5 डॉ एम.एस. कादर

अ. सा. 6 श्रीमती गायत्री, वैज्ञानिक सहायक

अ. सा. 7 तिरु मोहनदास

अ. सा. 8 तिरु श्रीनिवासन

अ. सा. 9 तिरु समरसपांडियन, प्रधान कांस्टेबल

अ. सा. 10 तिरु राजशेखर, पुलिस निरीक्षक

अ. सा. 11 तिरु रामू

अ. सा. 12 श्रीमती राजी

10. अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य के निम्नलिखित टुकड़ों पर भी भरोसा किया:-

प्रदर्श पी.1 (06.11.2007) – ग्राम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत।

प्रदर्श पी.2 (12.11.2007) – अभियुक्त के बयान में अ. सा. 1 के हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी.3 (12.11.2007) – ग्राम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर
हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी.4 (28.11.2007) – विसेरा रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.5 (06.11.2007) – शव परीक्षा प्रमाण पत्र।

प्रदर्श पी.6 (06.11.2007) – निरीक्षण गुमशुदगी रिपोर्ट में अ. सा. 7 के
हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी.7 (06.11.2007) – गुमशुदगी रिपोर्ट में अ. सा. 7 के हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी.8 (06.11.2007) – निरीक्षण गुमशुदगी रिपोर्ट में अ. सा. 8 के
हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी.9 (06.11.2007) – गुमशुदगी रिपोर्ट में अ. सा. 9 के हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी.10 (06.11.2007) – मुद्रित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी)।

प्रदर्श पी.11 (06.11.2007) – निरीक्षण गुमशुदगी रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.12 (06.11.2007) – कच्चा रेखाचित्र।

प्रदर्श पी.13 (06.11.2007) – गुमशुदगी रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.14 (06.11.2007) – जाँच रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.15 (06.11.2007) – एम.ओ.8 की वसूली के लिए विशेष प्रतिवेदन।

प्रदर्श पी.16 (12.11.2007) – ग्राम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अभियुक्त का
बयान।

प्रदर्श पी.17 (12.11.2007) – वी.ए.ओ. प्रतिवेदन।

प्रदर्श पी.18 (12.11.2007) – इकबालिया बयान में स्वीकार्य हिस्सा।

प्रदर्श पी.19 (12.11.2007) – एम.ओ.1, 2 और 9 की वसूली के लिए
गुमशुदगी रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.20 (12.11.2007) – परिवर्तन रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.21 (13.11.2007) – रासायनिक परीक्षा के लिए अनुरोध।

प्रदर्श पी.22 (14.11.2007) – रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालय पत्र।

प्रदर्श पी.23 (28.11.2007) – जीव विज्ञान रिपोर्ट।

प्रदर्श पी.24 (28.02.2008) – सीरोलॉजी रिपोर्ट।

11. मौखिक साक्ष्य के अभिलेखन के निष्कर्ष पर, यहां – अपीलकर्ता का आगे का बयान संहिता की धारा 313 के तहत दंडाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया।
12. मौखिक के साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विचारण न्यायालय ने यह राय बनाई कि यह मामला गैर-इरादतन हत्या का है। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर यहां अपीलकर्ता को धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 1 का लाभ देना उचित समझा कि यह मामला गंभीर और अचानक उकसावा का था, और तदनुसार, यहां – अपीलकर्ता को धारा 304 (भाग 1) भा.दं.वि. के तहत दंडनीय अपराध का दोषी

ठहराया और उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।

13. अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया। उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रही। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की।
14. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।
15. हमने अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेयस कौशल और तमिलनाडु राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी. कुमानन को सुना है।
16. हम इस तथ्य का संज्ञान लेते हैं कि यहां – अपीलकर्ता ने 4 वर्ष का कारावास काटा है। घटना सन 2007 की है।
17. धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 1 की लागू होने की क्षमता के संबंध में हमारे अपने विचार हैं। हालाँकि, राज्य हमारे समक्ष अपील में नहीं है।
18. धारा 300 का अपवाद एक बताता है कि एक गैर-इरादतन हत्या, हत्या नहीं है यदि अपराधी, गंभीर और अचानक उकसावा द्वारा आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के दौरान, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसने उकसावा दिया या गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है।
19. यह सुस्थापित है कि धारा 300 के अपवाद 1 को लागू किया जा सकता है जब अभियुक्त को गंभीर और अचानक उकसावा द्वारा आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित दर्शाया गया हो जो उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया हो जिसकी मृत्यु कारित की गई है।
20. प्रत्येक और हर उकसावा अपराध को हत्या से कम करके गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित नहीं करेगा। उकसावा गंभीर और अचानक दोनों होना चाहिए। अपवाद का लाभ उठाने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा किया गया

कार्य गंभीर के साथ ही अचानक उकसावा की एक सहज प्रतिक्रिया थी जिसने उसे आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दिया। यदि उकसावा गंभीर है लेकिन अचानक नहीं है, तो अभियुक्त इस अपवाद का लाभ नहीं ले सकता है। इसी तरह, वह अपवाद को आहूत नहीं कर सकता है जहाँ उकसावा अचानक होने पर भी गंभीर नहीं है।

21. *मैनसिनी बनाम लोक अभियोजन निदेशक* (1942 ए.सी. 1 में प्रतिवेदित) में, विस्काउंट साइमन ने टिप्पणी की:

"यह सभी उकसावा नहीं है जो हत्या के अपराध को गैर-इरादतन हत्या में कम कर देगा। उकसावा, उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, ऐसा होना चाहिए जो अस्थायी रूप से भड़के हुए व्यक्ति को आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दे, जिसके परिणामस्वरूप वह उस अवैध कार्य को करता है जो मृत्यु कारित करता है। "यह प्रश्न तय करने में कि यह मामला था या नहीं, उस कार्य की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा अपराधी मृत्यु कारित करता है, उकसावा और उस कार्य के बीच बीते समय पर जो मृत्यु कारित करता है, उस अंतराल के दौरान अपराधी के आचरण पर, और उसके मन की स्थिति को दर्शाने वाली अन्य सभी परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए": स्टीफन की आपराधिक विधि की डाइजेस्ट, अनुच्छेद 317। लागू किया जाने वाला परीक्षण एक उचित व्यक्ति पर उकसावा के प्रभाव का है, जैसा कि आपराधिक अपील न्यायालय ने रेक्स बनाम लेसबिनी 7 में निर्धारित किया था, ताकि एक असामान्य रूप से उत्तेजनीय या झगड़ालू व्यक्ति उस उकसावा पर भरोसा करने के लिए हकदार नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति को उस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता जैसा उसने किया। परीक्षण को लागू करने में, यह विशेष महत्व का है (क) विचार करना कि क्या पर्याप्त अंतराल बीत गया है जबसे उकसावा हुआ है ताकि एक उचित व्यक्ति को शांत होने का समय मिल सके, और (ख) उस

उपकरण को ध्यान में रखना जिससे गैर-इरादतन हत्या की गई थी, क्योंकि उकसावा से उत्पन्न आक्रोश की गर्मी में, एक साधारण प्रहार से जवाब देना, एक छिपे हुए कटार जैसे एक घातक उपकरण का उपयोग करने से बहुत अलग बात है। संक्षेप में, प्रतिशोध का तरीका उकसावा से एक उचित संबंध रखना चाहिए यदि अपराध को गैर-इरादतन हत्या में कम किया जाना है।”

22. मामले को अपवाद 1 के दायरे में लाने के लिए, निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:

- (i) मृतक ने अभियुक्त को उकसावा दिया होगा;
- (ii) उकसावा गंभीर होना चाहिए;
- (iii) उकसावा अचानक होना चाहिए;
- (iv) अपराधी, अचानक उकसावा के कारण, आत्म-नियंत्रण की अपनी शक्ति से वंचित हो गया होगा;
- (v) उसने आत्म-नियंत्रण की शक्ति के वंचित होने की निरंतरता के दौरान मृतक को मारा होगा; और
- (vi) अपराधी ने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की होगी जिसने उकसावा दिया या गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की होगी।

23. दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि अपवाद 1 को आहूत किया जा सके, अभियुक्त को निम्नलिखित परिस्थितियों को स्थापित करना होगा:

- (i) एक उकसावा था जो गंभीर और अचानक दोनों था;
- (ii) ऐसे उकसावा ने अभियुक्त को आत्म-नियंत्रण की अपनी शक्ति से वंचित कर दिया था; और
- (iii) जिस समय अभियुक्त आत्म-नियंत्रण की अपनी शक्ति से इस प्रकार वंचित था, उसने पीड़ित की मृत्यु कारित की थी।

24. धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 1 के तहत अपने मामले को लाने के लिए

निम्नलिखित घटक हैं:

(i) उकसावा अचानक था; (ii) उकसावा गंभीर था; और (iii) आत्म-नियंत्रण का नुकसान। इन तीन घटकों पर एक-एक करके विचार किया जा सकता है:

(i) उकसावा अचानक था या नहीं, इसमें अधिक कठिनाई पेश नहीं आती है। 'अचानक' शब्द में दो तत्व शामिल हैं। पहला, उकसावा अपेक्षित नहीं होना चाहिए। यदि एक अभियुक्त बाद की गैर-इरादतन हत्या को उचित ठहराने के लिए एक उकसावा प्राप्त करने की पूर्व में योजना बनाता है, तो उकसावा को अचानक नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, उकसावा और गैर-इरादतन हत्या के बीच का अंतराल संक्षिप्त होना चाहिए। यदि उकसावा देने वाले व्यक्ति को उकसावा के एक मिनट के भीतर मार दिया जाता है, तो यह अचानक उकसावा का एक मामला है। यदि व्यक्ति को उकसावा के छह घंटे बाद मारा जाता है, तो यह अचानक उकसावा का एक मामला नहीं है।

(ii) मुख्य कठिनाई यह तय करने में है कि एक निश्चित उकसावा गंभीर था या नहीं। अभियुक्त द्वारा केवल एक बयान कि उसने उकसावा को गंभीर माना, न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय को यह तय करने के लिए एक परीक्षण करना होगा कि उकसावा गंभीर था या नहीं। यह तय करने के लिए एक अच्छा परीक्षण कि एक निश्चित उकसावा गंभीर था या नहीं, यह है: "क्या एक उचित व्यक्ति ऐसे उकसावा के परिणामस्वरूप आत्म-नियंत्रण खो सकता है?" यदि उत्तर सकारात्मक है, तो उकसावा को गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि उत्तर नकारात्मक है, तो उकसावा गंभीर नहीं है। इस संदर्भ में, 'उचित व्यक्ति' अभिव्यक्ति का मतलब एक सामान्य या एक औसत व्यक्ति है। एक उचित व्यक्ति आदर्श व्यक्ति या सिद्ध प्राणी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति कभी-कभी गुस्सा खो देता है। इसलिए, यह कहने में कोई विसंगति नहीं है कि, एक उचित व्यक्ति गंभीर उकसावा के परिणामस्वरूप आत्म-नियंत्रण खो

सकता है। एक उचित या सामान्य या औसत व्यक्ति एक कानूनी कल्पना है। उचित व्यक्ति समाज से समाज में अलग-अलग होगा। एक न्यायाधीश को इस मामले में अपने व्यक्तिगत मानक लागू नहीं करने चाहिए। प्रशिक्षण से, एक न्यायाधीश एक धैर्यवान व्यक्ति होता है। लेकिन उचित व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति का व्यवहार का मानक वही होना आवश्यक नहीं है जो न्यायाधीश का स्वयं है। विचाराधीन उचित व्यक्ति उस समाज का एक सदस्य है, जिसमें अभियुक्त रह रहा था। इसलिए, अभियुक्त की शिक्षा और सामाजिक स्थितियाँ प्रासंगिक कारक हैं। गाली-गलौज का एक सामान्य आदान-प्रदान एक सामान्य घटना का मामला है। एक उचित व्यक्ति केवल गाली-गलौज के एक सामान्य आदान-प्रदान के कारण आत्म-नियंत्रण नहीं खो देता है। इसलिए, न्यायालय गाली-गलौज के एक सामान्य आदान-प्रदान को गंभीर उकसावा के लिए एक आधार के रूप में नहीं मानते हैं। दूसरी ओर, अधिकांश समाजों में, व्यभिचार को एक बहुत गंभीर मामला माना जाता है। इसलिए, न्यायालय व्यभिचार को गंभीर उकसावा के लिए एक आधार के रूप में मानने के लिए तैयार हैं।

(iii) आत्म-नियंत्रण के नुकसान का प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से यह तय करने में आता है कि एक विशेष उकसावा गंभीर था या नहीं। इसलिए, यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त को गंभीर और अचानक उकसावा प्राप्त हुआ था, तो न्यायालय आम तौर पर यह मानने के लिए तैयार होता है कि गैर-इरादतन हत्या तब की गई थी जब अभियुक्त आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित था। कुछ मामलों में, अभियोजन के लिए यह साबित करना संभव हो सकता है कि अभियुक्त ने गंभीर उकसावा के बावजूद एक शांत दिमाग के साथ हत्या की। लेकिन ऐसे मामले दुर्लभ होंगे। इसलिए, जब अभियुक्त ने गंभीर और अचानक उकसावा स्थापित कर दिया है, तो न्यायालय आम तौर पर मानेंगे कि उसने धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 1 के तहत उस पर पड़े भार का निर्वहन कर दिया है।

25. न्यायालय का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? उकसावा ऐसा होना चाहिए जो केवल

एक जल्दबाज और गर्म मिजाज या अतिसंवेदनशील व्यक्ति को नहीं, बल्कि सामान्य समझ और शांतता वाले व्यक्ति को परेशान करे। न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या अभियुक्त के समान स्थिति में रखा गया एक उचित व्यक्ति वही उकसावा प्राप्त करने पर उसी तरह से व्यवहार करता जिस तरह से अभियुक्त ने व्यवहार किया। यदि यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त की कार्रवाई दिए गए उकसावा की गंभीरता या परिमाण के सभी अनुपात से बाहर थी, तो मामला अपवाद के तहत नहीं आएगा। मामला केवल तभी अपवाद के तहत आएगा जब न्यायालय यह मानने में सक्षम हो कि प्रस्तावित उकसावा दिए जाने पर, हर सामान्य व्यक्ति उन परिस्थितियों में उसी तरह से व्यवहार या कार्य करेगा जिसमें अभियुक्त रखा गया था, कार्य किया।

26. विस्काउंट साइमन के शब्दों में: "उकसावा से संबंधित पूरा सिद्धांत इस तथ्य पर निर्भर करता है कि यह आत्म-नियंत्रण का एक अचानक और अस्थायी नुकसान पैदा करता है, या पैदा कर सकता है, जिसके द्वारा द्वेष, जो मारने या गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचाने के इरादे का गठन है, नकार दिया जाता है। परिणामस्वरूप, जहाँ उकसावा मारने या गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचाने के एक वास्तविक इरादे को प्रेरित करता है, वहाँ सिद्धांत कि उकसावा हत्या को गैर-इरादतन हत्या में कम कर सकता है, शायद ही कभी लागू होता है।"

27. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 अभियुक्त पर सबूत का भार डालती है। एक अपवाद होने के कारण, अपवाद 1 द्वारा कवर की गई परिस्थितियों को साबित करने का भार अभियुक्त पर है। जहाँ अभियोजन प्रथम दृष्ट्या साबित करता है कि कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई और अभियुक्त याचना करता है कि मामला अपवादों में से एक के तहत आता है, तो यह उसे साबित करने के लिए है।

28. यह अभियुक्त पर है जो अपवाद 1 के तहत अपने मामले को लाकर अपने अपराध

की प्रकृति को कम करना चाहता है, यह साबित करने के लिए कि उसके द्वारा प्राप्त उकसावा ऐसा था जो उचित रूप से आत्म-नियंत्रण से वंचित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है, और यह कि मारने का कार्य तब हुआ जब नियंत्रण की वह अनुपस्थिति अस्तित्व में थी और उचित रूप से इसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। (संदर्भ: रतनलाल और धीरजलाल का अपराध कानून, 24 वाँ संस्करण)।

29. यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय मामले को गैर-इरादतन हत्या के दायरे में लाना चाहते थे, तो यह धारा 300 भा.दं.वि. के अपवाद 4 को आहूत कर सकता था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि घटना पूर्व-नियोजित या पूर्व-चिंतित नहीं थी। अपीलकर्ता और उसके दोस्त एक फिल्म देखने गए थे। वे देर रात के घंटों में घर लौट रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म समाप्त होने के बाद और लौटते समय, उन्होंने पुल के नीचे कुछ आराम करने का फैसला किया। मृतक भी पुल के नीचे सो रहा था। हालाँकि, अभियोजन का यह मामला है कि मृतक नशे की हालत में था। वास्तव में, ऐसा कुछ भी संकेत नहीं है कि मृतक शराबी था। हालाँकि, घटना के चश्मदीद गवाह और वह भी अभियुक्त के दोस्तों के अलावा कोई और नहीं थे जिन्होंने अभियोजन द्वारा जाँच किए जाने पर गवाही दी कि मृतक नशे की हालत में था।
30. मृतक ने कुछ बुरे शब्द कहे और ऐसा लगता है कि उसने यहां अपीलकर्ता पर हाथ भी उठाया और थप्पड़ भी मारा। हालाँकि, केवल उसी से मामले को गंभीर और अचानक उकसावा के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
31. घटना एक पल के उत्तेजना पर हुई। कार्य पूर्व-नियोजित या पूर्व-चिंतित नहीं था। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता के हाथों में कोई हथियार नहीं था। उसने पुल के नीचे पड़ा एक सीमेंट का पत्थर उठाया और वही मृतक के सिर पर मारा। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया या क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य नहीं किया।

32. जैसा भी हो, हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बाधित करने के इच्छुक नहीं हैं।
33. हम इस राय के हैं कि न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे यदि विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा को पहले ही काटी गई अवधि तक कम कर दिया जाता है।
34. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम सजा की अवधि को पहले ही भुगती जा चुकी अवधि तक कम करते हैं।
35. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाते हैं।
- मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

† हेडनोट्स तैयार की गई: नीति रिचहरिया, मानद सहयोगी संपादक
(सत्यापित द्वारा: लिज मैथ्यू, वरिष्ठ अधिवक्ता)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।